सूचना
यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नही हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते है तो इस नम्बर पर संपर्क करे-
7620469536
औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

epaper:suffahdailynews.com

दैनिक
सुफ्फा
आम आदमी की आवाज़..।
मुख्य संपादकः सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन
R.N.I. MAHHIN/2017/70719

हुसैनी
फॅमिली रेस्टॉरंट
शादी तथा पार्टी की ऑर्डर लिये जाते है

Email:suffaakl@gmail.com ■ साल ९ वा ■ अंक ८० ■ बुधवार ७ मई २०२५ ■ अकोला ■ पृष्ठ ४ ■ मूल्य ३ रूपये

एक नजर

मुंबई के लिए 'येलो अलर्ट', जिलों में की गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी

मुंबई-
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सप्ताह के अंत तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कोंकण क्षेत्र के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुंबई में आर्द्रता का स्तर बढ़ गया है और सोमवार को आसमान में बादल छाए रहे। वहीं आज यानी मंगलवार और बुधवार को तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोनों दिन मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले दो दिनों में राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। सोमवार को सांताक्रूज में अधिकतम तापमान ३३.७ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोलाबा में अधिकतम तापमान ३४.२ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलाबा में दिन के दौरान ७० प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली-
सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे कंधे चौड़े हैं और हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा- हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया था। पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में महिला माओवादी मारी गई

नई दिल्ली-
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चल रहे बड़े पैमाने पर माओवादी विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह मुठभेड़ सोमवार को छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ियों के आसपास के जंगल में हुई। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ के साथ ही, २१ अप्रैल को सुरक्षा बलों द्वारा अभियान शुरू किए जाने के बाद से अब तक क्षेत्र में चार महिला माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभियान में विभिन्न इकाइयों के लगभग २४,००० जवान शामिल थे। सुंदरराज ने बताया कि सोमवार को मुठभेड़ स्थल से एक .३०३ राइफल भी बरामद की गई। २४ अप्रैल को करेंगुट्टा पहाड़ियों पर तीन महिला माओवादियों को मार गिराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई। बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में से एक कहा जा रहा यह अभियान, जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

महाराष्ट्र में ४ महीने में होंगे निकाय चुनाव
इलेक्शन नोटिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली-
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह रिजर्वेशन हो गया है, जो लोग इसमें चढ़ गए हैं, वे दूसरों को आने नहीं देना चाहते हैं। इस मामले में अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में ध्ंं रिजर्वेशन मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्यों कुछ ही वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए? बाकी लोगों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि इस पर विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारी स्थानीय निकाय के पदों पर बैठे हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ४ महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए। ४ हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। २०२२ के पहले की आरक्षण की व्यवस्था के मुताबिक चुनाव होंगे। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय के चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से इंदिरा जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायत में चुनी हुई लोकल बॉडी नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को अदालत में बुलाया है।

जानें कहां-कहां है चुनाव पेंडिंग?
महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित २९ नगर निगमों (महानगरपालिका), २५७ नगर पालिकाओं, २६ जिला परिषदों और २८९ पंचायत समितियों में चुनाव पेंडिंग है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर फैसला लेने का आग्रह किया था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने रिट दायर कर मांग की है कि पंचायत चुनाव यह तो ओबीसी आरक्षण के साथ हो या बिना रिजर्वेशन के हो। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को २७ प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अध्यादेश फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अदालत ने पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई। एण ने साफ (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

महायुति एक साथ लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव, 'मिनी विधानसभा चुनाव' जैसा दृश्य

मुंबई-
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ महायुति स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ लड़ेगी। अहिल्यानगर में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि एक-दो स्थानीय निकायों में अलग चुनाव लड़ने के बारे में फैसला हो सकता है। लेकिन नीतिगत रूप से महायुति एकजुट होकर ही स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में स्थानीय निकायों का चुनाव कराने के बारे में आदेश दिया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य चुनाव आयोग से निकाय चुनावों की तैयारी करने के लिए आग्रह किया जाएगा। महाराष्ट्र में साल २०२४ के लोकसभा चुनाव और साल

२०२४ के विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में तीसरा मौका होगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में शिवसेना (शिंदे) और राकांपा (अजित) के अलावा छोटे घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय किया तो ये चुनाव 'मिनी विधानसभा चुनाव' जैसा दृश्य उत्पन्न करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की नई पीढ़ी के लिए ताजी बयार बनकर आया है। करीब एक दशक बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव सभी दलों को नई पीढ़ी (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

पीएम मोदी को तीन दिन पहले से थी पहलगाम हमले की जानकारीः खड़गे

रांची -
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 'संविधान बचाओ रैली' में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने २२ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि पहलगाम हमले से तीन दिन पहले ही पीएम मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुरक्षा में चूक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। खुफिया अलर्ट के बावजूद क्यों नहीं उठाए सुरक्षा कदम?

रांची में सभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि पहलगाम हमले से तीन दिन पहले सरकार को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी, इसके बावजूद आवश्यक सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने तो अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके चलते २६ निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन्होंने इस चूक की जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए कहा कि जब सरकार खुफिया विफलता स्वीकार कर रही है, तो उसे मौतों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम का समर्थन करती है, लेकिन सरकार को सुरक्षा उपायों में चूक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी, तो वही सूचना सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस बल को क्यों नहीं दी गई? खरगे ने बोला मोदी सरकार की नीतियों पर सीधा हमला रैली में खरगे ने मोदी सरकार की आर्थिक और रोजगार नीतियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि देश में ३० लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरने की कोई पहल नहीं की जा रही है, ताकि गरीबों को नौकरी न मिल सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति 'PSU बंद करो और गरीबों की नौकरी छीनो' की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को महीनों (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को मात दी

मुंबई-
कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) की बंद कमरे में बैठक पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आज पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति यह है कि कोई भी देश उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और न ही उसके परमाणु हथियार और सिंधु जल समझौते के निलंबन पर हमले की धमकी का भारत पर कोई असर होता है। अकबरुद्दीन ने कहा, बहुपक्षीय संगठनों का इस्तेमाल करके दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का पाकिस्तान का प्रयास नया नहीं है। हमने इसे कई बार देखा है। इस बार उसने ६० वर्षों में पहली बार एक ऐसे एजेंडा पेश करने

की कोशिश की, जिस पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। वह है भारत-पाकिस्तान सवाल। भारत-पाकिस्तान सवाल पर आखिरी बार औपचारिक चर्चा १९६५ में हुई थी। पाकिस्तान ने सोचा कि इसके जरिए वह भारत-पाकिस्तान के मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाकर चर्चा का विषय बना सकता हैं। (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी अफसर विनय नरवाल के घर पहुंचे राहुल गांधी

नई दिल्ली-
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को पहलगाम टेरर अटैक में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी ने उनके परिवार को सांत्वना दी। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने भी करनाल में नरवाल के परिवार की ओर से आयोजित 'श्रद्धांजलि सभा' में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद के परिवार को ५० लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। करनाल के रहने वाले विनय नरवाल का पिछले महीने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया

गया। उनके पिता राजेश नरवाल और मामा ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। शहीद के पिता राजेश नरवाल ने सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्याय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नुकसान असहनीय और अपूरणीय हैं (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

इतिहास में पहली बार ग्रामीण इलाकों में कैबिनेट मीटिंग, फडणवीस सरकार के ११ बड़े फैसले

सैफई-
पुण्यश्लोका अहिल्यादेवी होल्कर की त्रिशताब्दी जयंती मनाने के लिए चौंडी में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। राज्य के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की बैठक ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज चौंडी (अहिल्यानगर) में आयोजित बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी

होल्कर के जीवन पर आधारित एक व्यावसायिक मराठी और बहुभाषी फिल्म का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच, सांस्कृतिक विकास निगम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। चूंकि यह एक व्यावसायिक फिल्म है, इसलिए आवश्यक व्यय बजटीय मांगों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आदिशक्ति अभियान लागू करेंगे/आदिशक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के संबंध में समाज में संवेदनशीलता पैदा करेंगे। अभियान के माध्यम से जागरूकता एवं आन्दोलन खड़ा किया (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

२९५ जिलों में होगी मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय से नया अपडेट सामने आया

नई दिल्ली-
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की तैयारी की जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच बन रहे खतरों को देखते हुए कल बुधवार को देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है. शुरुआती जानकारी ये बात सामने आई थी कि ऐसे २४४ जिले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि २९५ जिलों में ये मॉक ड्रिल कराया जाएगा. संख्या में बदलाव इसलिए है, क्योंकि साल २०१० तक सिविल डिफेंस के लिए तैयार जिलों की संख्या

२४४ थी. उसके बाद कुछ जिलों का बंटवारा हो गया, नए जिले बन गए, जिसके चलते सिविल डिफेंस जिलों की संख्या में इजाफा हो गया और इसमें ५१ जिले बढ़ गए. इस हिसाब से अब २९५ जिलों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है. पांच दशकों से भी लंबे समय के बाद यह पहली बार है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस कर्मियों से मॉक ड्रिल कराया (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और नियुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की

नई दिल्ली-
न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कार्यरत न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा और न्यायिक नियुक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार (५ मई) की शाम को न्यायालय ने अपने ३३ में से २१ न्यायाधीशों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें प्रभावशाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सभी पांच सदस्य शामिल हैं.

न्यायालय ने संकेत दिया कि बाकी १२ न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा प्राप्त होने पर अपलोड कर दी जाएगी. बार एंड बेंच के अनुसार, यह निर्णय हाल ही में न्यायिक जवाबदेही विवादों के बीच आया है, जिसमें विशेष रूप से मार्च के मध्य में आग लगने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी.

ज्ञात हो कि इससे पहले २००९ के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव में पहले से ही न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति मुख्य न्यायाधीश को घोषित करने की जरूरत होती थी, हालांकि यह स्वैच्छिक था और विवरण ऑनलाइन प्रकाशित नहीं किए गए थे. १ अप्रैल के नए निर्णय में अब इन विवरणों को न्यायालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करना

आवश्यक है. संपत्ति घोषणाओं के साथ-साथ न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के लिए न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित की है. यह दस्तावेज उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य और केंद्र सरकारों और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की विशिष्ट भूमिकाओं को रेखांकित करता है.

न्यायालय ने ९ नवंबर, २०२२ से ५ मई, २०२५ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में विस्तृत डेटा भी अपलोड किया है. रिकॉर्ड में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम, पृष्ठभूमि (बार या न्यायिक सेवा), सिफारिश और नियुक्ति की तारीखें, आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला) और मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ कोई पारिवारिक संबंध शामिल हैं.

यह प्रकाशन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की १३ मई को होने वाली आगामी सेवानिवृत्ति से पहले हुआ है. गौरतलब है कि हाल की घटनाओं ने न्यायिक जवाबदेही पर जोर दिया है. एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रारंभिक रिपोर्ट (संशोधनों के साथ) सार्वजनिक कर दी थी. नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की (**शेष पृष्ठ ३ पर**)

अग्रलेख

बेकाबू ट्रोलर्स

मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत न फैलाने की अपील करने वाली हिमांशी नरवाल और एक बच्ची से दरिंदगी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों की मर्यादाहीन भाषा पर एतराज करने वाली शैला नेगी के साथ जिस तरह की अभद्र टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, वह पूरे देश के लिए शर्मनाक और अफसोसजनक है। ट्रोलिंग करने वालों ने सारी मर्यादा तोड़ दी। एक महिला की गरिमा का भी ख्याल नहीं किया। सोशल मीडिया पर किसी की ट्रोलिंग अब बेहद आम हो चुकी है। ट्रोलर्स ऐसी लहर की तरह बर्ताव करते हैं, जिसके सामने कोई नियम-कायदा, नैतिकता या मर्यादा नहीं टिकती। हिमांशी इसी ट्रेंड का शिकार हुईं और यही देखने को मिला नैनीताल में शैला नेगी के साथ। जरूरत यह थी कि समाज इन दोनों हिम्मती और विवेकशील लड़कियों का साथ देता। लेकिन इन्हें गालियां और धमकियां मिल रही हैं। संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। लेकिन इस आजादी का एक निश्चित दायरा है। यह अभिव्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता और गरिमा पर चोट करने वाली नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हुए कई लोग इस बात को भूल जाते हैं। उन्हें बात रखने की अपनी आजादी तो नजर आती है, सामने वाले का अधिकार और उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रहता। किसी की बातों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसे व्यक्त करने का तरीका शालीन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर गाली-गलौज या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जब ऐसी भाषा पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नहीं चलती, तो सोशल मीडिया पर कैसे चल सकती है, जिसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अगस्त २०२३ में शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व विधायक और अभिनेता एस वी शेखर को महिला पत्रकारों के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी लिखने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय इसके प्रभाव और पहुंच को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पर ही हिमांशी और शैला को सपोर्ट करने वाले भी हैं। यह सुखद तो है, पर समस्या का हल नहीं। सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस को लेकर सोचने की जरूरत है। रेप की धमकियों का सामना कर रहीं शैला का यह सवाल सबके लिए है कि लोग किस बात को लेकर सड़क पर उतरे थे और कहां पहुंच गए।

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होने मुद्रक - औरंगज़ेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिंटींग प्रेस,** हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता.जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफीस : **दैनिक सुफ्फा,** जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नही. (पी.आर.बी.ॲक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

इजरायल की हवाई नाकेबंदी करेंगे... मिसाइल हमले के बाद यमन के हूतियों की नई धमकी, इंटरनेशनल एयरलाइंस को चेतावनी

सना-

ईरान समर्थित यमन के हूती चरमपंथियों ने इजरायल के खिलाफ हवाई नाकेबंदी की घोषणा की है। इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हूतियों ने एक बयान में कहा कि वे इजरायल के हवाई अड्डों को मिसाइल से निशाना बनाना जारी रखेंगे। हूतियों ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेतावनी को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। हूतियों ने कहा कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा, 'हम इजरायल के हवाई अड्डों, विशेष रूप से तेल अवीव के पास (बेन गुरियन) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बार-बार निशाना बनाकर घेराबंदी करेंगे।' हूती समूह से जुड़े अल-मसीरा टीवी पर जारी एक बयान में सारी ने कहा, 'हम गाजा के

खिलाफ आक्रमण का विस्तार करने के फैसले के जवाब में इजरायली दुश्मन पर एक व्यापक हवाई नाकाबंदी की घोषणा करते हैं।'हूती सैन्य प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों से किसी भी इजरायली हवाई अड्डे के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द करने का आग्रह किया। इससे पहले रविवार सुबह हूती समूह ने मध्य इज़राइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी थी, जो टर्मिनल ३ के पास गिरी थी। इस हमले में छह लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे।इज़राइली सेना ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने मिसाइल को रोकने का प्रयास किया लेकिन विफल रही। बाद में इसने एक अलग बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विफलता का संभावित कारण इंटरसेप्टर मिसाइल के साथ 'तकनीकी समस्या' थी। हूती मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी थाड सिस्टम भी दागा गया, लेकिन यह भी नाकाम रहा था। इसके बाद सोमवार रात में इजरायल ने करीब २० लड़ाकू विमानों के यमन के हुदैदाह शहर पर बड़ा हमला बोला था।

फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार हुए ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका को झटका कैसे?

पेरिस:

ब्रिटेन और फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। अभी तक दुनिया के चुनिंदा देशों ने ही फिलिस्तीन को एक देश माना है। दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन नाम का कोई देश मौजूद भी नहीं है। उसकी जगह दो स्वतंत्र इलाके गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जरूर नजर आते हैं, जो इजरायल के दो किनारों पर स्थित हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप के दो प्रमुख देशों से मान्यता मिलने के बाद जल्द ही फिलिस्तीन नाम का एक स्वतंत्र देश दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता क्यों दे रहे हैं।रूसी मीडिया स्पुतनिक से बात करते हिए यूके स्थित डाइमेंशन्स फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के शोधकर्ता और भू-राजनीतिक विश्लेषक मेहमत राकिपोग्लू ने बताया कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता है – लेकिन यह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का एक कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश जा सकता है कि लंदन और पेरिस अमेरिका और इजरायल के मोहरे नहीं हैं या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं।ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारें अचानक फिलिस्तीनी कारणों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती हैं – गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों पर घरेलू विरोध और वैश्विक आक्रोश ने उन्हें मजबूर कर दिया है।

सभी पश्चिमी राजधानियों में यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी नेताओं के लिए अब चुप रहना कोई विकल्प नहीं है।विश्लेषक ने कहा कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस पश्चिमी मूल्यों को कायम रखने का दावा करते हैं, तो गाजा में इजरायल के युद्ध पर चुप रहना नैतिक दुविधा पैदा करता है, क्योंकि आप मानवाधिकारों का उपदेश देते हुए व्यापक पैमाने पर जनहानि को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की वतन वापसी, एयरपोर्ट से ही BNP का बड़ा ऐलान, मोहम्मद यूनुस की बढ़ेगी टेंशन!

ढाका-

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए चार महीने तक लंदन में रहने के बाद ढाका लौटी हैं, वह इस साल जनवरी में देश से बाहर गई थीं। जिया का उनकी पार्टी BNP के नेताओं ने ढाका में एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया है। जिया की वापसी से देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है। जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से अंतरिम सरकार पर इसी साल चुनाव कराने का दबाव बनाया जा रहा है। जिया की वापसी से यूनुस पर ये दबाव बढ़ेगा, जो अभी तक चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ती नहीं दिखी है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका एयरपोर्ट पर BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि जिया की वापसी से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। उन्होंने कहा, 'यह हमारी पार्टी और देश के लिए खुशी का क्षण है। लोकतंत्र के लिए इस अहम समय में जिया की उपस्थिति देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि खालिदा जिया की वापसी से लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता खुलेगा। उन्होंने साफ इशारा किया कि उनकी पार्टी चुनाव की मांग पर जोर देगी। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में छात्रों के विरोध के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के अधीन है। अंतरिम सरकार पर देश में चुनाव कराकर विजेता दल को सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी है लेकिन अंतरिम सरकार की चुनाव कराने की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चुनावों की कोई तारीख नहीं बताई है।

उन्होंने सुधारों के बाद अगले साल जून तक चुनाव होने की उम्मीद जताई है। अब उन पर ँज़ की पार्टी का दबाव बढ़ेगा, जो जिया के देश में ना होने की वजह से कुछ नरम पड़ गई थी। खालिदा जिया और शेख हसीना १९९१ से बारी-बारी से देश की प्रधानमंत्री रही हैं। बीते तीन दशकों में यही दोनों नेता बांग्लादेश की सबसे अहम सियासी चेहरे हैं। खालिदा जिया तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। दो बार उन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और एक बार कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनीं। हसीना के शासन में जिया को दो भ्रष्टाचार के मामलों में १७ साल की जेल हुई थी। बीते साल अंतरिम सरकार आने के बाद उनको रिहा किया गया था। जिया पूर्व सैन्य प्रमुख राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की विधवा हैं। जियाउर्रहमान की १९८१ में हत्या कर दी गई थी।

अब बातचीत का कोई मतलब नहीं... इजरायल के गाजा प्लान पर भड़का हमास, बंधक डील पर वार्ता से इनकार

गाजा:

इजरायल के गाजा में मानवीय सहायता रोकने और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के प्लान पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल की ओर से गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने की योजना का खुलासा करने के बाद हमास ने कहा है कि अब उनसे किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमास का कहना है कि इजरायल की ओर से जिस तरह का रुख दिख रहा है, उससे नहीं लगता कि हम उनके साथ युद्धविराम या बंधक डील पर कोई बातचीच कर सकते हैं।फिलिस्तीनी गुट हमास के वरिष्ठ अधिकारी बसीम नईम ने कहा है कि इजरायल की ओर से भूखमरी को युद्ध बनाने तक वे किसी नए प्रस्ताव पर बात नहीं करेंगे। इजरायल की ओर से गाजा के लोगों तक भोजन जैसी जरूरी चीजें पहुंचने से रोका जा रहा है और पूरे क्षेत्र पर कब्जे की योजना बनाई जा रही है। इसी पर हमास ने कहा है कि इस तरह के प्लान के साथ बातचीत नहीं चल सकती है।इजरायल और हमास के बीच गाजा में अक्टूबर, २०२३ से युद्ध चल रहा है। ७ अक्टूबर, २०२३ से अब तक गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली सेना द्वारा किए गए नरसंहार और चल रहे आक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर ५२,६१५ शहीद और ११८,७५२ घायल हो गई है। चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि इस टोल में १८ मार्च से २,५०७ शहीद और ६,७११ घायल हैं, जो युद्ध विराम समझौते के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण के फिर से शुरू होने के बाद हुआ है। इजरायल के हमलों में गाजा में भारी तबाही हुई लेकिन वह अपने सभी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा है। ऐसे में अब वह गाजा में हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है।इजरायल ने गाजा को लेकर नए प्लान को मंजूरी दी है। इस प्लान में गाजा की आबादी को विस्थापित करने और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करते हुए नाकाबंदी करना शामिल है। इस योजना की ब्रिटेन, फ्रांस और UN ने अमानवीय कहते हुए आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में मौतें और तबाही होगी। हमास ने भी ऐसे प्लान के बाद इजरायल से बातचीत की संभावना को नकार दिया है।इजराइल का कहना है कि वह गाजा से अपने सभी बंधकों को वापस लाना चाहता है .

हम आज भी अपने रुख पर कायम...अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता पर ईरान का बड़ा बयान, क्या बनेगी बात!

तेहरान-

ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर वह अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर ईरान से परमाणु हथियार के मुद्दे पर गंभीरता से बात करता है तो कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। ईरान ने कहा है कि वह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी बातचीत करने को तैयार है क्योंकि वह चीजों को शांति से हल करने का पक्षधर है। ईरान और अमेरिका के बीच ३ मई को होने वाली चौथी दौर की परमाणु वार्ता को 'जरूरी वजहों' से टाल दिया गया था। इससे दोनों देशों के बीच कुछ समय पहले शुरू हुए वार्ता सवालों के घेरे में है। इस पर

इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि हमने कई दौर की बातचीत में हिस्सा लेकर अपना रुख साफ किया है और अब भी अपने रुख पर कायम हैं।ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान बातचीत के समय को लेकर लचीला रुख अपनाए हुए है। वह ओमान से बातचीत के अगले दौर के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहा है। ओमान इस मामले में ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है। बगई ने कहा कि हमारे लिए अमेरिका की बातचीत करने वाली टीम बहुत अहमियत रखती हैं। बगई ने यह भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के परमाणु वार्ता पर विरोधाभासी बयान इस मुद्दे को हल करने में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद तेहरान के अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान अपने देश में यूरेनियम का संवर्धन करने के अधिकार पर कायम है लेकिन ये सिर्फ देश के विकास से जुड़े कामों के लिए है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में कहा है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम का आयात करना चाहिए। उसे अपने देश में यूरेनियम का संवर्धन नहीं करना चाहिए।अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता नहीं किया तो वह सैन्य हमला करेंगे। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दोनों देशों ने हाल ही में इस मुद्दे के हल के लिए बातचीत शुरू की है।

पाकिस्तान की संसद में पास हुआ ऐसा प्रस्ताव जिसके बाद 'जंग' छिड़ना तय

इस्लामाबाद-

भारत पाकिस्तान तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. पूरे विश्व में चिंता है कही ये तनाव जंग में न बदल जाए, लेकिन कुछ डेवेलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जिन के बाद 'जंग' छिड़ना तय हो गया है. पाकिस्तान की सांसद में एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें भारत के पानी रोकने और पहलगाम हमले में पाकिस्तान पर आरोप लगाने की निंदा की गई है.

प्रस्ताव में भारत के पानी रोकने को 'एक्ट ऑफ वार' मानने की बात कही गई है. इसका मतलब है कि भारत का पानी रोकना जंग की

शुरुआत करना होगा. वहीं भारत पर भी पाकिस्तान की नि धमकियों का कोई असर नहीं दिख रहा है और वह पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी कर चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह चुके है कि पहलगाम के दोषियों को उनकी कल्पाना से भी कठोर सजा दी जाएगी.भारत सरकार ने पंजाब से जाने वाली झेलम और चिनाब का पानी रोकने के लिए कदम उठाए हैं, कुछ खबरों के मुताबिक भारत ने काफी हद तक पाकिस्तान का पानी रोक भी दिया है. सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि पाकिस्तान के सियालकोट में झेलम नदी का पानी सूख गया है, जिससे पाकिस्तान की खेती को बड़ा नुकसान हो सकता है. भारत के इस कदम से पाकिस्तान प्यास के साथ-साथ भूख से भी मरेगा.बैठक में संयुक्त राष्ट्र के चीफ गुटेरेस ने कहा कि वह पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद के गुस्से को समझते हैं. उन्होंने कहा, 'नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है – और जिम्मेदार लोगों को विश्वसनीय और वैध तरीकों से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.'गुटेरेस जोर दिया की दोनों देसों को सैन्य टकराव से बचना चाहिए और ये अब अधिकतम संयम और पीछे हटने का समय है. लेकिन इस बैठक में भारत के पानी रोकने को लेकर किसी देश द्वारा निंदा नहीं की गई है.

इतिहास में पहली बार ग्रामीण इलाकों में कैबिनेट मीटिंग, फडणवीस सरकार के ११ बड़े फैसले

नई दिल्ली-
● कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, लिंग भेद को समाप्त कर बालिकाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण करना, यौन एवं शारीरिक शोषण को रोकना तथा हिंसा मुक्त परिवार एवं समाज का निर्माण करना, कुरीतियों को मिटाना, महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक विकास करना.

● आदिशक्ति अभियान का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने वाली ग्राम पंचायतों को आदिशक्ति पुरस्कार दिए जाएंगे ● इस अभियान के क्रियान्वयन पर १०.५० करोड़ खर्च किए जाएंगेधनगर समुदाय के छात्रों को एक प्रसिद्ध अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने की योजना का नाम राजा यशवंतराव होलकर के नाम पर रखा गया है। यह योजना अब 'यशवंत विद्यार्थी योजना' के रूप में लागू होगी। ● प्रतिवर्ष १०,००० विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। ● इसके लिए अब तक ?२८८.९२ करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। ● राजा यशवंतराव होलकर ने १७९७ से १८११ के बीच शैक्षिक उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। गुरुकुल जैसी पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। सैन्य शिक्षा में अनुशासन, नैतिकता और नेतृत्व गुण शामिल थे। शिक्षा सभी के लिए खुली कर दी गई। महल में लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाएं स्थापित की गईं। अब यह योजना उनके नाम पर है।धनगर समुदाय के मैट्रिक के बाद की शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के लिए राजस्व विभाग के मुख्यालय में छात्रावास बनाने की योजना का नाम 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर छात्रावास योजना' रखा गया है। ● राज्य में राजस्व विभाग के मुख्यालय में धनगर समुदाय के मैट्रिक के बाद की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। ● इनमें से प्रत्येक छात्रावास की क्षमता २०० होगी। इसमें लड़कों के लिए १०० और लड़कियों के लिए १०० सीटें हैं। ● नवी मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, नागपुर, अमरावती में हॉस्टल ● नासिक में काम शुरू हो गया है, पुणे, नागपुर में जल्द ही शुरू होगा ● इन हॉस्टलों का नाम अब पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर छात्रावास योजना रखा गया हैपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर द्वारा निर्मित घाटों, कुओं, जल वितरण प्रणाली का सर्वेक्षण करेगा और उनके संरक्षण के लिए एक विशेष योजना को लागू करेगा। ● राज्य में ३ ऐसी ऐतिहासिक झीलें (चांदवाड़, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी) ● राज्य में १९ ऐसे कुएं ● राज्य में कुल ६ ऐसे घाट ?? राज्य में कुल ६ ऐसी टंकिया ● कुल ३४ ऐसे जलाशयों की मरम्मत, गाद निकालना, पुनरोद्धार, सौंदर्यीकरण आदि किया जाएगा। ● इसके लिए ७५ करोड़ खर्च किए जाएंगे

अहिल्यानगर जिले में १०० छात्रों की क्षमता वाला एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज और ४३० बिस्तरों वाला एक संलग्न अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इस कॉलेज का नाम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होगा। ● इसके लिए ४८५.०८ करोड़ खर्च किए जाएंगे। ● इसके लिए जिला सामान्य अस्पताल को भूमि, जनशक्ति उपलब्ध कराई जाएगी।राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर की तीन सौवीं जयंती मनाने और उनके मंदिर पुनर्निर्माण कार्य को श्रद्धांजलि देने के लिए ५५०३.६९ करोड़ की मंदिर विकास योजना ● चौंडी में पुण्यश्लोका अहिल्यादेवी होल्कर स्मारक स्थल का संरक्षण और संरक्षण: ६८१.३२ करोड़ ● अष्टविनायक गणपति मंदिरों का नवीनीकरण: १४७.८१ करोड़ ● श्री क्षेत्र तुलजाभवानी देवी मंदिर विकास योजना: १८६५ करोड़ ● श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर विकास योजना: २५९.५९ करोड़ ● श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास योजना: २७५ करोड़ ● श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना: १४४५.९७ करोड़ ● श्री क्षेत्र माहुरगढ़ विकास योजना: ८२९ करोड़अहिल्यानगर में बालिकाओं और महिलाओं के लिए नई आईटीआई शुरू की जाएगी

● राहुरी, जिला अहिल्यानगर में वरिष्ठ स्तर का सिविल न्यायालय स्थापित करने का निर्णय

● ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन (वीएसटीएफ) के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे मिशन महाग्राम कार्यक्रम की अवधि को २०२२-२५ के स्थान पर २०२८ तक बढ़ाने का निर्णय

खजूर और दूध के फायदे

खजूर को Date Palm कहते है. खजूर जो की एक फल है कई लोग ऐसे बड़े ही प्यार से खाते है. कई लोगो का ये मनपसंद होता है लेकिन कई लोगो को खजूर बिलकुल पसंद नहीं होता है कई लोग तो खजूर का नाम सुनते ही उनके मुँह में पानी आ जाता है और कई लोग इसे अपने उेबईल्ये में शामिल भी करते है और अभी तो फिर रमजान भी चल रहे है इन दिनों में खजूर खाने के फायदे बहुत होते है कई लोग इसे इसके पोषक तत्वों के कारण भी खाते है खजूर कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. खजूर विभिन्न Vitamins, मिनरल्स और Fibers, Oils, Calcium, सल्फर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, कॉपर और मैग्नेशियम जैसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हैं Human Body के लिए बहुत जरुरी तत्व है.

कब्ज से बचाव

ज्यादातर लोगो को कब्ज की परेशानी होती है और कब्ज होने वाले लोगो के लिए खजूर वरदान की सामान है खजूर को आप रातभर पानी में भिगो कर रख दे सुबह तक ये सिरप की तरह हो जाते है और इस तरह खाने से आपको काफी लाभ होगा इसमें सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो आपको खाने का श्दनसहू बेहतर कर देता है जिस कारण आप कब्ज की ईदंतसे से राहत पाते है.

वजन घटाने की अपने कई सारे नुस्खे देखे है और दिए भी जाते है लेकिन अगर आप वजन बढ़ाना चाहते है लेकिन आपके पास इनके लिए कोई खास ऊग्जे नहीं होगी पर आज हम आपको बताते है खजूर में प्रोटीन, विटामिन्स और शुगर होते है इस खजूर को आप ककड़ी के पेस्ट के साथ खा सकते है इसमें बैलेंस्ड रहते है १ किलोग्राम खजूर में ३००० कैलोरी होती है इसे आप रोज नियमित रूप से ले आप को बहुत फायदा मिलेगा. खजूर खाने के फायदे के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिये.

जैसा की आप जानते ही है की आज कल ण्ैहमी की बीमारी किस हद तक बढ़ गई है जिसे रोकने के लिए रिसर्च जारी है

नाक बहने का इलाज

घरेलू उपाय सर्दियो में जब नाक बहती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है. आप ना ही सो पाते हैं, ना ही खा पाते हैं और आपका किसी चीज पर ध्?यान नहीं लगता. यह उनके लिये भी बहुत झेलने वाला होता है जो आपके आस पास मौजूद होते हैं. बहती हुई नाक को रोकने के लिये अपने पास टिशू पेपर रखने के बजाए, आप नाक बहने का इलाज या उपचार का प्रयोग करें ऐसा करने से आपकी बहती हुई नाक एक दम बंद हो जाएगी और आप फिर से फ्रेश फील करेंगे. इन घरेलू उपचार की मदद से आपकी बहती हुई नाक रुक जाएगी और आपका पूरा स्वास्थ्य अच?छा हो जाएगा. मौसमी जुकाम के इलाज में हल्दी काफी फायदेमंद है. बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें, इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा व तत्काल आराम मिलेगा.

यदि नाक बंद है तो दालचीनी, कालीमिर्च, इलायची और जीरे के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लें और इन्हें सूंघें. जिससे से आप को काफी फायदा होगा. हम सभी सर्दी के मौसम में कई तरह की बीमारी के लपेटे में आ जाते है जैसे सर्दी जुकाम, खासी और नाक से पानी आना यानी नाक बहने जैसी समस्याओ से परेसान रहते है. सर्दी एक आम बीमारी है, लेकिन समय पर अगर इसका इलाज न हो जाये तो ये बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले लेता है. सर्दी जुकाम के कारन बहुत सी परेशानी जैसे बुखार आना, सिर दर्द और बदन दर्द का सामना करना पड़ जाता है.

सर्दी जुकाम से हमारी नाक कभी-कभी बंद हो जाती है जिससे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और कभी-कभी तो नाक बहुत बहती है जिससे हम कोई भी काम करंट समय बहुत दिक्कत में आ जाते है. जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है और बुखार भी आ जाता है साथ में बदन दर्द भी हो जाता है. इसलिए आप को इसके कोई पक्का इलाज करना जरूरी है. और यदि आप नाक बहने के इलाज को करना चाहते तो आपको घर में मौजूद कुछ बस्तुओं का उपयोग करना होगा जिससे आप को बहुत जल्दी आराम मिल जायेगा.

लहसुन के इस्तेमाल करके आप खुद ही अपना इलाज कर सकते है इसके लिए आपको लहसुन का प्रयोग करना होगा. लहसुन में बहुत से एंटीबायोटिक गुण पाए जाते है जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है अगर किसी की नाक बंद हो गयी हो या जुकाम के कारण नाक से पानी आ रहा हो तो लहसुन का इस्तेमाल बहुत लाभ पहुचता है. आपको इसका इस्तेमाल बताये. आप लहसुन की कली को और हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर उबाल ले. जब ये पक जाये तो इसे उतार दे और ठंडा होने दे. जब ठंडा हो जाये तो इसे आप सेवन करे ऐसा करने से आपकी नाक खुल जाएगी और अगर पानी आ रहा हो तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है.

सबसे बेहतरीन और आसान इलाज तो यही है कि नमक के पानी से गरारा करें क्योंकि नमक में लवणीय गुण होता है. इस उपाय को करने के लिए आप १ कप पानी में १ चम्मच नमक मिला कर घोल लें. इस पानी से ३० सेकेंड के लिये गरारा करें आपको राहत मिलेगी. इससे आपके नाक बहने का इलाज भी हो जायेगा और आपके गले की खराश भी दूर जाएगी. और नाक बहने का इलाज करने करने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते है. और सरसो के तेल की महक बहुत असरदार होती है. और इसको सुघने से आपकी नाक बहने का इलाज आसानी से हो जायेगा और आप आसानी से साँस लेने में भी आसानी होती है. और जिससे नाक बिल्कुल साफ हो जाती है.

और इसका इस्तेमाल आप कुछ इस प्रकार कर सकते है. १ चम्मच सरसों का तेल कटोरी में रख कर १० सेकेंड के लिये माइक्रोवेव में रखें. फिर एक-एक बूंद अपनी दोनो नाकों में डालें. इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा. २ चम्मच सूखी अजवायन को बारीक पीस लें और उसे साफ रुमाल के बीच में रख कर बांध दें. इस पोटली को नाक पर रख कर सूंघे। जब भी नाक बहे तब इसे सूंघे. और एक कप में १/४ चम्मच हल्दी डालें और १ कप पानी उबालें। उबले पानी को हल्दी के साथ मिक्स करें। १० मिनट के बाद हल्दी को पानी से छान लें और गरमा गरम चाय पियें। जब तक नाक बहे तब तक हर दिन २ कप चाय ऐसे ही बना कर पियें. आपके नाक बहने का इलाज हो जायेगा.

अदरक में कई सारे एंटीसेप्टिक गुण होते है. और यदि आप अदरक की चाय का सेवन करते है तो आपको काफी फायदा है. अदरक की चाय सबसे बेस?ट चाय है और यह तुरंत बन जाती है. एक कप में ३ टुकड़े अदरक के डाल कर १ कप गरम पानी डालें. इसमें दालचीनी भी डालें और जब ये अच्छी तरह से उबाल जाएँ तो इसे गरमा गर्म पीएं ऐसा करने से आपकी बहती हुई नाक ठीक हो जाएगी और आपको गले सम्बन्धी रोग भी ठीक हो जाते है इसलिए हो सके तो इसका सेवन कम से कम दिन में दो से तीन बार अवश्य करें ये आपके लिए काफी फायेदमंद होगा.

Name Change

I have change my name From **Old Name: Mohammad Zishan Abdul Fahim** New Name : **Zeeshan Fahim Shaikh**
Address: Hediya Pura Shivaji Nagar June Shahar Old City Akola 444002

(पृष्ठ १ पर से..)

महाराष्ट्र में ४ महीने में होंगे निकाय चुनाव

कर दिया कि बिना डेटा एकत्रित किए पंचायत चुनावों में आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट पालन किए बिना राज्य सरकार का ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महायुति एक साथ लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव,

के नेताओं की एक बड़ी फौज उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार २०१७ में हुए थे। बड़ी संख्या में ऐसे भी नगर निगम हैं, जहां २०१५ में अंतिम बार चुनाव हुए थे। उसके बाद से स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और चुनाव नहीं करवाए जा सके। इसलिए राजनीतिक दलों में चुनाव लड़कर किसी छोटे से छोटे सदन में भी पहुंचने वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी बिना चुनाव लड़े ही निकल गई है।इसका असर स्थानीय विकास कार्यों पर भी पड़ता रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि है ही नहीं। ए-श्रेणी की मुंबई महानगरपालिका सहित सभी स्थानीय निकायों में प्रशासन आईएएस अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जिन तक आम आदमी की पहुंच ही नहीं होती। महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं की संख्या २८, नगरपालिकाओं की १८५ से १९० के बीच, जिला परिषद ३४ एवं ३८५ पंचायत समिति हैं। यदि राज्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन सभी निकायों में चुनाव कराने का निर्णय करता है, तो लंबी अवधि के बाद होनेवाले ये चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव का दृश्य उत्पन्न करेंगे।संभवतः ये चुनाव में राज्य चुनाव आयोग को दो या दो से अधिक चरणों में कराने पड़ें। क्योंकि अब राज्य में सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या ही १० के करीब पहुंच चुकी है, और स्थानीय निकायों में तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक होती है। पिछले वर्ष हुए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक दलों में तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तनाव की हद पहुंच सकती है। चुनाव आयोग को इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा।मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आते ही महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन मिलकर ही चुनाव मैदान में उतरेगा। फडणवीस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं चार महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के फैसले से प्रसन्न हूं। मैंने राज्य चुनाव आयोग को इसकी तैयारियां करने को कह दिया है।कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राज्य में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की शुरुआत बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है । स्थानीय निकायों के चुनावों के ज़रिए उस आवाज़ को मज़बूती मिलती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में नगर निगमों और परिषदों को चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय नियुक्त प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है। इससे शासन में जनता की सीधी भागीदारी कम हो गई है एवं नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद टूट गया है।

पीएम मोदी को तीन दिन पहले से थी

तक वेतन नहीं मिल रहा, जबकि सरकार दावा करती है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत से ही विकास का आकलन किया जाना चाहिए।खरगे ने झारखंड की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि 'इंडिया' गठबंधन की सरकार को जो समर्थन मिला है, वह जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक मजबूत और जनहितैषी सरकार चल रही है, जो जनता से किए वादों को निभा रही है रैली के दौरान खरगे ने देश की एकता और संविधान की रक्षा के लिए शहीद हुए नेताओं को भी याद किया। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि देश सबसे पहले है, इसके बाद धर्म, जाति और पार्टी आती है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

लेकिन यह केवल एक दिखावा था।पूर्व राजनयिक ने कहा, पाकिस्तान सार्वजनिक कूटनीति पर ज्यादा फोकस करता है। असल में वह इन मंचों का उपयोग अपने देश की छवि को सुधारने के लिए के लिए करता है, न कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर वार्ता के लिए। इसलिए उसका प्रयास विफल हो गया। दिखावा काम नहीं आया। सुरक्षा परिषद ने उसके मामले को स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो महीनों से १५ देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम कर रहा था। फिर पता चला कि जो वह चाहता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ने बताया कि सुरक्षा परिषद इस तरह से काम करता है.. सबसे पहले प्रस्ताव आता है, फिर अध्यक्षीय बयान आता है, फिर प्रेस बयान और अंत में सुरक्षा परिषद के प्रमुख प्रेस से मौखिक रूप से कुछ कहते हैं। इन चारों में से कोई भी बात इस बैठक के बाद नहीं हुई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो भी कोशिश की, वो पूरी तरह विफल रही।आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला।उन्होंने कहा, जो होना था, वही हुआ – इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की दुनिया में पाकिस्तान को एक गंभीर और भरोसेमंद देश नहीं माना जाता। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की कोशिशें सिर्फ दिखावे और प्रचार के लिए होती हैं, ना कि किसी गंभीर संवाद या समाधान के लिए। वह सिर्फ मंच पर बोलना चाहता है, लेकिन असली बातचीत में रुचि नहीं रखता।उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच की पाकिस्तान की मांग का चीन द्वारा समर्थन किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। अकबरुद्दीन ने कहा, यह एक ऐसा खेल है जिसे पाकिस्तान नियमित रूप से खेलता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें वह लड़खड़ा जाता है। यह एक ऐसा खेल है, जिसमें उसका एकमात्र सदाबहार मित्र चीन है। लेकिन बाकी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, वह पाकिस्तान को उसकी वास्तविकता के रूप में पहचानती है।

पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी

दरअसल विनय नरवाल की शादी हाल ही में हुई थी। १६ अप्रैल को उनका रिसेप्शन था। कोच्चि में तैनात विनय नरवाल छुट्टी पर जम्मू और कश्मीर गए थे। वह अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में थे। तभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। दिवंगत नौसेना अधिकारी की पत्नी ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उन्होंने अपने पति को एक ऐसा व्यक्ति बताया जो सम्मान के साथ जिया और साहस की विरासत छोड़ गया। २२ अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले में २६ लोग मारे गए थे।

२९५ जिलों में होगी मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय से नया अपडेट सामने आया

जा रहा है. इससे पहले साल १९७१ में भारत- पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के समय ही इतने बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल कराया गया था. कहा जा रहा है किये मॉक ड्रिल युद्ध से पहले का अब तक का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल होगा.इस मेगा मॉक ड्रिल के अलावा कई संगठन और स्वयं सहायता ग्रुप अपने-अपने स्तर पर भी मॉक ड्रिल में शामिल हो रहे हैं जिसके लिए उन्होंने स्थानीय और राज्य स्तर पर संबद्ध अधिकारियों को जानकारी दी है.जानकारी ये भी है कि बीजेपी के सांसदों से भी आम नागरिक की तरफ इस ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया है. छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं.केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने यहां पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों ने बताया कि इसके लिए सभी डीसीपी से तैयारियों के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा गया है.सूत्रों का कहना है कि पुलिस उपायुक्तों ने दिल्ली में गश्त तेज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी हैं. दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और नियुक्ति के.........

जांच कर रही तीन न्यायाधीशों की समिति ने रविवार (४ मई) को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है.जस्टिस वर्मा, जिन्हें बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, कोर्ट के अनुसार इसका संबंध उन पर चल रही जांच से नहीं था. इस मामले में उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है.

मुंबई के लिए 'येलो अलर्ट', जिलों में की गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी

गई, जबकि सांता क्रूज़ में ६३ प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले दो दिनों में वातावरण में नमी और बढ़ सकती है। इससे अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।किन-किन जिलों में अलर्ट

इस दौरान मुंबई के साथ-साथ पालघर और ठाणे जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। रायगढ़ में भी मंगलवार और बुधवार को 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। बुधवार को रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, पुणे, सतारा और सांगली जिलों में बुधवार तक 'येलो अलर्ट' है। गुरुवार को कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। छत्रपति संभाजी नगर, बीड, जालना में दो दिन तथा नांदेड़, लातूर में बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना

मौसम विभाग के रिटायर्ड अधिकारी माणिकराव खुळे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के ऊपर वामावर्त घूम रही चक्रवाती हवाओं और अरब सागर में डेढ़ किलोमीटर की ऊंचाई तक दक्षिणावर्त घूम रही चक्रवाती हवाओं के दोनों के मिलने से राज्य भर में ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलेशन के कारण बेमौसम बारिश की तीव्रता भी बढ़ गई है। हालांकि लोगों को लू से राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को किया खारिज

तिवारी की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे।निशिकांत दुबे के बयान पर मचा था बवालवकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल याचिका में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को न्यायपालिका के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया गया है। साथ ही याचिका में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।बीजेपी ने सांसद दुबे के बयान से कर लिया था किनारा

हालांकि, बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान से किनारा कर लिया था। पार्टी ने उनके बयानों को उन नेताओं की व्यक्तिगत राय करार दी थी और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया था।

वहीं, जस्टिस बीआर गवई ने एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने के आरोप को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मु' भेड़ में महिला माओवादी मारी गई

फाइटर्स और विशेष कार्य बल, छत्तीसगढ़ पुलिस की सभी इकाइयों; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा के जवानों के साथ-साथ अन्य को भी शामिल कर रहा है।यह अभियान माओवादियों की सबसे मजबूत सैन्य इकाई मानी जाने वाली बटालियन नंबर १ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और माओवादियों की तेलंगाना राज्य समिति के नेताओं की इलाके में मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया था। पुलिस के अनुसार, पहाड़ियों की श्रृंखला वाला यह घना वन क्षेत्र बटालियन संख्या १ का बेस बताया जाता है।सुंदरराज ने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ता या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में महिला माओवादी मारी गई छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चल रहे बड़े पैमाने पर माओवादी विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह मुठभेड़ सोमवार को छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ियों के आसपास के जंगल में हुई। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ के साथ ही, २१ अप्रैल को सुरक्षा बलों द्वारा अभियान शुरू किए जाने के बाद से अब तक क्षेत्र में चार महिला माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभियान में विभिन्न इकाइयों के लगभग २४,००० जवान शामिल थे। सुंदरराज ने बताया कि सोमवार को मुठभेड़ स्थल से एक .३०३ राइफल भी बरामद की गई।

संजय गांधी निराधार योजना की राशि नहीं मिलने से नागरिक परेशान

दस्तावेज जमा करने लगाने पड़ते हैं चक्कर पर चक्कर..सुफ्फा की टीम पहुंची तहसील

अकोला-(चांद रज़वी)

राज्य सरकार द्वारा संचालित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के अंतर्गत मिलने वाली मासिक सहायता राशि समय पर न मिलने के कारण अनेक लाभार्थी नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें खासतौर से विकलांग एवं बुजुर्ग लोगों का समावेश है। जिन्हें अकोला तहसील कार्यालय के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह योजना विशेष रूप से वृद्ध, निराश्रित, विकलांग और अत्यंत गरीब नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है किंतु नागरिकों को दस्तावेज जमा करने के लिए चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं।हाल ही में कई जिलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लाभार्थियों को पिछले दो से तीन महीनों से नियत राशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे उन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ नागरिकों ने बताया कि उन्हें दवाइयाँ, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। संजय गांधी निराधार योजना जैसी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवनरेखा होती हैं।

सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का वितरण समय पर सुनिश्चित करें, ताकि लाभार्थियों का भरोसा बना रहे और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस प्रकार की मांग इस दौरान की गई।

सहायता कक्ष आरंभ करने की मांग

उक्त मामले में दैनिक सुफ्फा को कई शिकायतें प्राप्त हुई थी।जिसमे खास तौर पर अशिक्षीत व बुजूर्ग लोग तहसील कार्यालय पहुंचते है वहांपर उन्हें काफी सहायता कक्ष नही होने के कारण काफी परेशानीयों का सामना करना पडता है। बुजुर्ग महिलाएं, विकलांग महिलाएं यह कार्यालय के बाहर हताश होकर बैठी हुई नजर आती है। पश्चात इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी से प्रतिक्रिया लेनी चाही तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया और फिर सर्वर ठीक होने का बताकर तहसील कार्यालय में बैठी हुई महिलाओं के दस्तावेज जमा किए एवं ओटीपी लेकर उन्हें फिर वहां से रवाना किया गया।

स्थानीय तहसील कार्यालय की अनदेखी

लाभार्थियों का कहना है कि जब वे स्थानीय तहसील कार्यालय में संपर्क करते हैं, तो उन्हें केवल 'तकनीकी कारणों' का बहाना बताकर घंटे तक बैठाया जाता है। एक वृद्ध महिला ने रोते हुए कहा की अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें मीना से अनुदान राशि नहीं मिल रही है। अब जब नहीं मिला, तो खाने-पीने तक की मुश्किल हो गई है।' दवाइयां खरीदना भी दुश्वार हो जाता है।ओटीपी के लिए घंटो तक बैठाया जाता है फिर बाद में सर्वर डाउन का बहाना बात कर भगा दिया जाता है। इस प्रकार की शिकायते भी प्राप्त हुई है।?इस स्थिति से त्रस्त नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से अपील की है कि तुरंत इस योजना के अंतर्गत लंबित अनुदान राशि वितरित की जाए और भविष्य में ऐसा विलंब न हो, इसके लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करेंगे। तथा दस्तावेज जमा करने में होने वाली खामियों को भी दूर किया जाए।

फिर लौटेगा जनता राज, खत्म होगा प्रशासक राज!

८ मार्च २०२२ अकोला महानगरपालिका की अवधि हुई थी खत्म

अकोला -

अकोला महानगर पालिका की अवधि खत्म दिनांक ०८ मार्च २०२२ को हो चुकी थी। जिसके बाद से अकोला में प्रशासक राज चल रहा था। बीच में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी आकर चले गए किंतु महानगरपालिका चुनाव पर किसी भी प्रकार का निर्णय ओबीसी के मुद्दे के चलते नहीं हो पाया था। किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिया गया निर्णय बड़ा निर्णय बताया जा रहा है जिनका स्वागत स्थानीय राजकीय गलियारों में किया जा रहा है। यदि राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय किया तो ये चुनाव 'मिनी विधानसभा चुनाव' जैसा दृश्य उत्पन्न करेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की नई पीढ़ी के लिए ताजी बयार बनकर आया है।करीब एक दशक बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव सभी दलों को नई पीढ़ी के नेताओं की एक बड़ी फौज उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार २०१७ में हुए थे। उसके बाद से स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और चुनाव नहीं करवाए जा सके। इसलिए राजनीतिक दलों में चुनाव लड़कर किसी छोटे से छोटे सदन में भी पहुंचने वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी बिना चुनाव लड़े ही निकल गई है। इसका असर स्थानीय विकास कार्यों पर भी पड़ता रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि है ही नहीं। प्रशासन आईएएस अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जिन तक आम आदमी की पहुंच ही नहीं होती। महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं की संख्या २८, नगरपालिकाओं की १८५ से १९० के बीच, जिला परिषद ३४ एवं ३८५ पंचायत समिति हैं।

यदि राज्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन सभी निकायों में चुनाव कराने का निर्णय करता है, तो लंबी अवधि के बाद होनेवाले ये चुनाव मिनी विधानसभा चुनाव का दृश्य उत्पन्न करेंगे।संभवतः ये चुनाव में राज्य चुनाव आयोग को दो या दो से अधिक चरणों में कराने पड़ें। क्योंकि अब राज्य में सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या ही १० के करीब पहुंच चुकी है, और स्थानीय निकायों में तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी अधिक होती है।

पिछले वर्ष हुए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक दलों में तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तनाव की हद पहुंच सकती है। चुनाव आयोग को इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा।

जरूरी सड़क मरम्मत और नदियों की गहराई बढ़ाने के कार्य पूरे करें

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अधिकारियों को निर्देश

अकोला-

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज अकोला में राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यक मरम्मत और नदियों व नालों की गहराई बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गडकरी एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में अकोला आए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और जानकारी ली तथा कुछ स्थानों पर निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानकों के अनुसार सभी आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में जलसंपन्नता की दृष्टि से नदियों और नालों का गहराईकरण आवश्यक है और इन कार्यों को गति दी जानी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गडकरी का अकोला विमानतल पर स्वागत

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह ९:४० बजे शिवणी हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस अवसर पर जिला प्रशासन और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत के समय विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकळे, विधायक वसंत खंडेलवाल आदि उपस्थित थे।प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी अजित कुंभार, जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बी. एस. साळुंखे ने उनका स्वागत किया। उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे, तहसीलदार सुरेश कव्हळे एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दलित बस्ती के निधि को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ का स्थगन आदेश

अकोला-

अकोला जिला परिषद अंतर्गत सत्र २०२४-२०२५ के दलित बस्ती योजना के अंतर्गत निधि को अकोला जिला परिषद की समाज कल्याण समिति ने सितंबर २०२४ में नियमानुसार और अनुमोदित नियोजन के तहत मंजूरी दी थी। इस निधि के वितरण के लिए पूर्ण प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, अकोला (महाराष्ट्र शासन) को नियमानुसार प्रस्तुत किया गया था।लेकिन दिनांक ३१ जनवरी २०२५ को आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में अकोला जिले के पालक मंत्री और जिलाधिकारी द्वारा दो अलग-अलग कार्यवृत्त तैयार कर, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस निधि को अन्य मदों में स्थानांतरित किया गया। इसके विरोध में पूर्व समाज कल्याण सभापति सौ. आम्रपालीताई खंडारे एवं कुछ सरपंचों ने मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की। मा. उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक २४०३/२०२५ की सुनवाई करते हुए दिनांक ५ मई २०२५ को इस निधि के वितरण पर स्थगन आदेश जारी किया है। साथ ही अकोला जिलाधिकारी को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।एक ही बैठक के दो भिन्न कार्यवृत्त बनाना, वैध प्रस्ताव के बावजूद उसे अनदेखा करना और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निधि को गैरकानूनी ढंग से अन्यत्र हस्तांतरित करना, इन सभी मुद्दों को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। निधि के ट्रांसफर में अत्यधिक जल्दबाजी की गई है, यह बिंदु भी याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के संज्ञान में लाया है। उनका कहना है कि जिन उद्देश्यों के लिए यह निधि सरकार द्वारा दी गई थी, उसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च करना पूरी तरह से गैरकानूनी है।इस याचिका में प्रतिवादी के रूप में अकोला के पालकमंत्री, समाज कल्याण विभाग के सचिव (मंत्रालय मुंबई), सहायक आयुक्त समाज कल्याण (अकोला), जिलाधिकारी अकोला, जिला नियोजन समिति के सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकोला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अकोला तथा कृषि विकास अधिकारी (जि.प. अकोला) को नामित किया गया है। इस याचिका की पैरवी उच्च न्यायालय, नागपुर में एडवोकेट आनंद राजन देशपांडे ने की। इस विषय पर आयोजित पत्रकार परिषद में वंचित बहुजन अघाड़ी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व महिला प्रदेश महासचिव मा. अरुंधतीताई शिरसाट, प्रदेश युवा महासचिव मा. राजेंद्र पातोडे, जिलाध्यक्ष मा. प्रमोद देंडवे, पूर्व समाज कल्याण सभापति सौ. आम्रपालीताई खंडारे, पूर्व गटनेता मा. ज्ञानेश्वर सुलताने, पूर्व जि.प. सदस्य विनोद देशमुख, पूर्व जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विकास सदांशिव, पराग गवई, अविनाश खंडारे, दिलीप शिरसाट आदि मान्यवर उपस्थित थे।

तेली समाज का पहला राज्य स्तरीय अधिवेशन शेगांव में

अकोला: -

संताजी नवयुवक मंडल की ओर से आगामी ११ मई को संत नगरी शेगांव में संगठन का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से तेली समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। विशेष बात यह है कि नेपाल से भी तेली समाज के सांसद और विधायक इस अधिवेशन में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घाटे ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी।आगे बोलते हुए सुभाष घाटे ने कहा कि इस अधिवेशन में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें समाज का एकत्रीकरण और आरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। ओबीसी समूह में तेली समाज का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर भी समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस बात की खंत उन्होंने व्यक्त की।इस अधिवेशन की शुरुआत में समाज के दिवंगत नेता, विधान परिषद सदस्य रामदास आंबटकर तथा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।पिछले कुछ समय में सरकार ने तेली समाज के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि तेलघाणी बोर्ड का गठन, संताजी आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना, श्री संत शिरोमणि जगदाळे महाराज संस्थान को 'ब' वर्ग दर्जा प्रदान करना और वहां स्मारक की स्थापना के लिए पहले चरण में ६८ करोड़ रुपये की निधि मंजूर करना।इन सभी निर्णयों के लिए सरकार का अभिनंदन किया जाएगा और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वहीं, पिछले तीन वर्षों से लंबित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव अब अगले चार महीनों में कराए जाने का जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त किया गया है।इस अवसर पर पत्रकार परिषद में प्रवीण झापर्डे, महेंद्र अकोटकर, ललित भगत, प्रो. प्रकाश डवले, ठाकुरदास चौधरी, योगेश गोतमारे, अनिल मालगे, एड. देवाशीष काकड़, गोपाल झापर्डे, राहुल धनभर, अरुण टिकले, रमेश गोतमारे, प्रशांत सेवतकर, नितीन वानखेड़े, दीपक इचे, दिलीप क्षीरसागर, राम जांबे, ज्ञानेश्वर रायपूरे, विनोद नालट आदि उपस्थित थे।

अकोला पुलिस बल के १३ पुलिस कर्मियों का पदोन्नति समारोह संपन्न

अकोला: -

अकोला पुलिस विभाग के ५ पुलिस हवालदारों को सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और ८ पुलिस सिपाहियों को पुलिस हवालदार पद पर पदोन्नति दी गई। कुल मिलाकर १३ पुलिस कर्मियों को सेवा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई। पदोन्नति के आदेश मिलने के पश्चात दिनांक ६ मई को पदोन्नति प्राप्त पुलिस कर्मियों का सपरिवार सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के चलते अकोला पुलिस विभाग में उत्साह व खुशी का वातावरण निर्माण हो गया था। यह कार्यक्रम अकोला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विजय हॉल में शाम ४:०० बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पदोन्नति वितरण से की गई। पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह और पुलिसकर्मियों के परिवारजनों के हाथो कंधे पर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक का बैज तथा सिपाहियों के कंधे पर हवालदार पद की पट्टी लगाई गई।यह कार्यक्रम पुलिस विभाग में उत्सव के रूप में अनुभव किया गया। पदोन्नति प्राप्त पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया और भावुकता के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति की शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम की सफलता के लिए आरक्षित पुलिस निरीक्षक गणेश जुमनाके और उनकी टीम ने विशेष मेहनत की। आभार प्रदर्शन और संचालन परी. पुलिस उपनिरीक्षक दीपक पवित्रकार ने किया।

देश के अमन-चैन के लिए दुआ की अपील, अकोला में हज हाजियों के लिए टीकाकरण शिविर संपन्न

अकोला: -

अकोला जिले से इस वर्ष हज यात्रा पर रवाना होने वाले हाजियों के लिए विशेष टीकाकरण एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जश्न पैलेस, अकोला बायपास पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह शिविर सरकारी महाविद्यालय एवं अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें हाजियों को आवश्यक टीके लगाए गए और यात्रा से जुड़ी स्वास्थ्य सलाह भी दी गई। मुख्य अतिथि आमदार साजिद खान पठान ने हाजियों को हज की मुबारकबाद दी और भावुक अपील करते हुए कहा,'आप सब अल्लाह के घर जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान के अमन, चैन और खुशहाली के लिए खास दुआ करें।'इस अवसर पर मुफ्ती हनीफ साहब (बलापुर) और मौलाना सबदर खान साहब भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने हाजियों को हज यात्रा के धार्मिक महत्व और उसकी तैयारी के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख समाजसेवक व आयोजक:अब्दुल वहाब, मिर्ज़ा ज़फ़र बेग, शफीक-उल-रेहमान, ज़फ़र भाई, अज़ीम भाई, आरिफ़ सर, अमन सर, जावेद ज़कारिया और नईम फ़राज़ सभी ने मिलकर शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। मंच पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. श्रेय अग्रवाल का विशेष सत्कार आमदार साजिद खान पठान द्वारा किया गया। डॉ. श्रेय ने हाजियों को चिकित्सा संबंधी सलाह देकर उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन शांतिपूर्ण और सेवाभावी वातावरण में हुआ, जिसे हाजियों और उनके परिजनों ने अत्यंत सराहा।